वर्ष 2004-2005 के लिए नई सेवा/सेवा के नवीन साधनों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण
Statement showing Details of New Service/New Instrument of Service for 2004-2005

क्रम. सं. विवरण	Sl. No. Particulars	बजट अनुमान 2004-2005 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2004-2005 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1 2	3 4	5	6	7
1. मांग सं.1 - कृषि एवं सहकारिता विभाग	**1. Demand No.1- Department of Agriculture and Cooperation**			
स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इन्डिया	State Farms Corporation of India	6.00	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए ऋण।	Loans for VRS.
राष्ट्रीय बीज निगम	National Seeds Corporation	4.00	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए ऋण।	Loans for VRS.
आन्ध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए कृषि में प्रशिक्षण (अंतवा)	Andhra Pradesh Training of Women in Agriculture (ANTWA)	1.00	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने नीदरलैण्ड सहित छोटे दानकर्ता से दिनांक 1.4.2004 से सहायता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस तरह डच द्वारा सहायता प्राप्त अंतवा परियोजना स्वदेशी समर्थन सहित वर्ष 2004-05 के दौरान जारी रहेगी।	Ministry of Finance(DEA) has decided to discontinue assistance from small donor including Netherlands w.e.f. 1.4.2004. As such Dutch assisted project ANTWA will be continued with domestic support during 2004-05.
कृषि में बायो-टेक्नोलॉजी का उपयोग	Biotechnology application in Agriculture	0.01	बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से संबंधित कृषि पर कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।	A token provision has been kept for implementation of recommendations of task force on Agriculture Related Application of Biotechnology.
वैश्विक कार्य योजना का कार्यान्वयन (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना)	Implementation of Global Plan of Action (Externally Aided Project)	0.19	एफएओ के लिए वनस्पति उत्पत्ति संबंधी संसाधनों के संरक्षण एवं उपयोग के लिए परियोजना एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में जापान सरकार से प्राप्त निधि से क्रियान्वित की जा रही है।	The project for conservation and utilization of Plant Genetic Resources for FAO is being implemented with funding from Govermment of Japan in Asia and Pacific Region.
एस.एफ.सी.आई. को अनुदान	Grants to SFCI	12.00	मंत्रिमंडल ने अरालम स्थित केन्द्रीय स्टेट फार्म को केरल सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है।	Cabinet has decided to handover the Central State Farm at Aralam to Govermment of Kerala.

क्रम. सं. विवरण	Sl. No. Particulars	बजट अनुमान 2004-2005 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2004-2005 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1 2	3 4	5	6	7
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	National Horticulture Mission	50.00	वर्ष 2010 तक बागवानी उत्पादन दुगना करने के लिए इस योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।	To double the Horticulture production by 2010, it is proposed to start this scheme.
लघु सिंचाई	Micro-Irrigation	10.00	यह एक नई योजना है।	This is a new scheme.
राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की मॉनिटरिंग	Monitoring of Pesticide residues at national level	5.00	मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा यह विषय कृषि और सहकारिता विभाग को आवंटित किया गया है। दसवीं योजना के लिए 24 करोड़ रुपए और वार्षिक योजना 2004-05 के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।	The subject has been allotted to Department of Agriculture & Cooperation by Cabinet Secretariat. Rs.24 crore has been proposed for Xth Plan and Rs.5 crore for Annual Plan 2004-05.
2. मांग सं. 4 - कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	**2. Demand No. 4 - Ministry of Agro and Rural Industries**			
पारम्परिक उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए निधि	Fund for modernisation of traditional industries	100.00	पारम्परिक उद्योगों की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	To meet the modernisation requirement of traditional industries.
3. मांग सं. 5 - परमाणु ऊर्जा	**3. Demand No. 5 - Atomic Energy**			
साइक्लोट्रोन द्वारा रेडियो आइसोटोप्स और उत्पादित रेडियो फार्मेसीक्यूटिक्लस के लिए प्रसंस्करण सुविधा	Processing Facility for Cyclotron produced Radio Isotopes and Radiopharmaceuticals	7.80	...	...
मेडिसन साइक्लोट्रोन	Medical Cyclotron	20.06	...	...
4.मांग सं.12 - वाणिज्य मंत्रालय	**4. Demand No. 12 - Department of Commerce**	0.01	यह प्रावधान खाद्यान्न निर्यात सबसिडी योजना के लिए है।	Provision is for the scheme of Food Grain Export Subsidy.
5. मांग सं. 16 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	**5. Demand No. 16 - Department of Information Technology**			
इलैक्ट्रानिकी	Electronics	1.00	मेगा फैब की स्थापना।	Setting up of Mega Fab.

क्रम. सं. विवरण	Sl. No. Particulars	बजट अनुमान 2004-2005 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2004-2005 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1 2	3 4	5	6	7
6. मांग सं. 20 - संस्कृति मंत्रालय	**6. Demand No. 20 - Ministry of Culture**	1.00	लाल बहादुर शास्त्री का जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए।	For celebration of Birth Centenary of Lal Bahadur Shastri.
7. मांग सं. 47 - स्वास्थ्य विभाग	**7. Demand No. 47 - Department of Health**			
भुज अस्पताल	Bhuj Hospital	3.00	भुज एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।	To provide medical facilities to earthquake victims of Bhuj and surrounding areas.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे छह अस्पताल-सह-शिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन	Establishment of six AIIMS type Hospitals-cum-Teaching Centres & Up-gradation of State Government Hospitals	60.00	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को लागू करना।	Implementation of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.
एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	Integrated Disease Surveillance Programme	30.00	राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न रोगों के लिए समेकित निगरानी का कार्यान्वयन।	Implementation of Integrated Surveillance for various diseases under National Health Programmes.
8. मांग सं. 59 - महिला और बाल विकास विभाग	**8. Demand No. 59 – Department of Women and Child Development**			
यौन-व्यापार के पीड़ितों के बचाव हेतु स्कीम	Scheme for Rescue of Victims of Trafficking	3.00	"यौन-व्यापार के पीड़ितों के बचाव हेतु स्कीम" नामक एक नई स्कीम की शुरूआत वर्ष 2004-05 के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है। सरकारी एजेंसियों को उनके कामों मे सहायता पहुंचाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा।	A new scheme "Scheme for Rescue of Victims of Trafficking" is proposed to be launched during the year 2004-05. The Non-Governmental Sector will also be involved to assist the Government Agencies in their work.
9. मांग सं.86 - पोत-परिवहन मंत्रालय	**9. Demand No. 86 - Ministry of Shipping**			
सागरमाला के तहत परियोजना	Projects under Sagarmala	24.48	सागरमाला कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के तटवर्ती पत्तनों का तीव्र क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण करना है। इस कार्यक्रम के तहत पत्तनों, अन्तर्देशीय जल यातायात, जहाजरानी सहित समुद्री क्षेत्र के त्वरित विकास संबंधी परियोजनाएं एवं तत्संबंधी कार्य आएंगे।	The Sagarmala Programme aims to achieve rapid capacity expansion and modernization of ports along India's coastline. Projects for accelerated development of maritime sector including Ports, Inland Water Transport, Shipping and related activities will be under the programme.

क्रम. सं. विवरण	Sl. No. Particulars	बजट अनुमान 2004-2005 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2004-2005 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1 2	3 4	5	6	7
10. मांग सं.88 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	**10. Demand No. 88 - Ministry of Social Justice and Empowerment**			
सामाजिक न्याय केंद्रों की स्थापना	Setting up of Social Justice Centres	5.85	यह प्रावधान देश में सामाजिक न्याय केंद्रों की स्थापना के लिए है।	Provision is meant for setting up of Social Justice Centres in the country.
11. मांग सं.89 - अंतरिक्ष विभाग	**11. Demand No. 89 - Department of Space**	70.00	चन्द्रयान-I - भारतीय चन्द्र मिशन के लिए।	For Chandrayan-I -Indian Lunar Mission.
12. मांग सं.90 - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**12. Demand No. 90- Ministry of Statistics and Programme Implementation**	69.50	मंत्रालय ने एक नई स्कीम "पांचवी आर्थिक जनगणना" का प्रस्ताव किया है जिसके लिए बजट अनुमान 2004-05 में 69.50 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। यह स्कीम सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों के माध्यम से लागू की जाएगी।	The Ministry has proposed a new scheme "Fifth Economic Census" for which an allocation of Rs.69.50 crore has been made in the BE 2004-05. The scheme would be implemented through Directorates of Economics and Statistics in all States and UnionTerritories.
13. मांग सं.93 - पर्यटन मंत्रालय	**13. Demand No. 93- Ministry of Tourism**	20.00	देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर मूलभूत ढांचागत सुविधाओं में सुधार करने के लिए।	For improving basic infra-structure facilities at important tourist places in the country.
14. मांग सं.103 - शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	**14. Demand No. 103 - Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation**	75.00	i) धारवी में गंदी बस्ती तथा दक्षिण मुम्बई में हवाई-अड्डा के साथ सड़क सम्पर्क सहित पुनर्वास।	i) Resettlement of Slum in Dharavi and along the road-side connecting airport with South Mumbai.
		4.00	ii) शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय रणनीति हेतु यू.एन.डी.पी. सहायता।	ii) UNDP Assistance for National Strategy for Urban Poor.